यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार: 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/75/2017 **दिनांक :** 04.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

15 सितम्बर 2017 का संसद मोर्चा – सामान्य सूचनायें एवं निर्देश

हमें एआईबीईए का परिपत्र पत्र संख्या 28/30/2017/30 दिनांक 02.09.2017 प्राप्त हुआ है जिसका अनूदित सार सम्बद्ध संगठनों, इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **दिल्ली चलो – बैंक बचाओ, देश बचाओ – 15 सितम्बर, 2017 को संसद के विशाल मोर्चा के लिए तैयार रहें – इसे एक बड़ी सफलता बनायें**

हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी यूनियनों ने देशभर में पहले ही हमारे सदस्यों को प्रेरित करते हुए योजना बना ली होगी कि किस प्रकार 15 सितम्बर, 2017 के संसद मोर्चा कार्यक्रम में उत्साही भागीदारी करनी है। हम अनुभव कर रहे हैं कि सरकार का रूख प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का है, और वह बैंकों के विलय की योजना हमारे सफल प्रतिरोध और 22 अगस्त, 2017 की हड़ताल को छोटा दिखाने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि एक वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी जाये।

कुछ दिन पहले, एक निजी बैंक के कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव ने कहा कि कुछ बैंक मर सकते हैं !

दो दिन पहले, सरकार ने एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय को प्रतियोगिता कमीशन अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान करता है।

कॉर्पोरेट खराब ऋणो को वसूल करने के कठोर उपाय करने के स्थान पर, सरकार बैंकों को बाध्य कर रही है कि वह कानूनी पचड़े में पड़ें भली प्रकार से जानते हुए कि यह एक समय लगाने वाली कानूनी प्रक्रिया है और इसके बाद भी पैसा बैंकों में वापस नहीं आयेगा बल्कि यह एक व्यापक बाहर हटाने की प्रक्रिया है और इसके प्रावधान बैंकों को और अधिक घाटे की ओर ले जायेंगे।

हाल ही में एक 900 करोड़ के कॉर्पोरेट ऋण की स्थिति में, मामला एनसीएलटी को भेजा गया और वहाँ इसे 54 करोड़ में तय करने को कहा गया (रू0 20 करोड़ तुरन्त भुगतान और बकाया रू0 34 करोड़ अगले 5 वर्षों में)।

जारी पृष्ठ 2

यह उन बहुत से मामलों का भविष्य हो सकता है जो एनसीएलटी में भेजे जाते हैं। बैंकों को इन बड़े ऋणों के लिए भारी राशि देनी पड़ेगी। बैंक संकट में आ जायेंगे। सरकार यही चाहती है।

इसलिए हमने अपने प्रयासों को दुगुना करते हुए आगामी कार्यक्रम के लिए अपने प्रयासों और सम्पर्कों को बढ़ा दिया है। हमें इस मोर्चे को एक बड़ी सफलता में बदलना है।

- हमारी इकाईओं की ओर से प्रत्युत्तर अत्यन्त उत्साहजनक है। लेकिन प्रदेशों को दिल्ली फैडरेशन को और हमें भागीदारों की सही संख्या सूचित करनी होगी जिससे कि वहां उचित तैयारियाँ की जा सकें।
- प्रदेश फैडरेशनों को अपने कमरों आदि की आवश्यकताओं के बारे में डीएसबीईएफ को बताना चाहिए और कृपया नोट करें कि आखिरी मिनट की व्यवस्थायें उनके लिए बहुत कठिन होंगी। इसलिए, जिन्होंने उन्हें सूचित नहीं किया है, कृपया हमें तुरन्त सूचित करें।
- दिल्ली का मौसम लगभग गर्म होगा और इसलिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं है।
- निकटतर्वी राज्यों जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब को उचित रूप से योजना बनानी चाहिए जिससे कि उनके भागीदार दिल्ली में 15 तारीख की सुबह समय से पहुंच जायें।
- जुलूस 15 तारीख को लगभग 10 बजे से प्रारम्भ होगा और इसलिए सभी भागीदार रामलीला मैदान पर सुबह 9 बजे तक पहुंच जायें।
- चूंकि यह यूएफबीयू का कार्यक्रम होगा, अगला बैनर यूएफबीयू का होगा जिसके पीछे यूएफबीयू के नेता होंगे।
- इसके उपरांत, एआईबीईए का बैनर होगा और उसके पीछे एआईबीईए के पदाधिकारी होंगे।
- इसके उपरांत हमारी प्रदेश फैडरेशनें उनके वर्णक्रमानुसार होंगी अर्थात् 1. असम, 2. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलगांना, 3. बिहार, 4. छत्तीसगढ़, 5. ईएमबीईए, 6. गोआ, 7. गुजरात, 8. महा गुजरात, 9. हरियाणा, 10. हिमाचल प्रदेश, 11. जम्मू एवं कश्मीर, 12. झारखण्ड, 13. कर्नाटका, 14. केरला, 15. मध्य प्रदेश, 16. महाराष्ट्रा, 17. मेघालय, 18. मणिपुर, 19. उड़ीसा, 20. पंजाब, 21. राजस्थान, 22. तमिलनाडु, 23. त्रिपुरा, 24. उत्तर प्रदेश, 25. उत्तरांचल, 26. पश्चिम बंगाल, 27. दिल्ली।
- इसके उपरांत, आईबौक, एनसीबीई, एआईबीओए, बैफी, इन्बैफ, इन्बौक आदि आयेंगे।
- जुलूस संसद मार्ग वित्तीय सेवा प्रभाग, वित्त मंत्रालय के सामने पहुंचेगा जहां जनसभा आयोजित होगी।
- सभी प्रदेश फैडरेशनें स्थानीय भाषा में अपने प्लेकार्डस ला सकते हैं। डीएसबीईएफ द्वारा अंग्रेजी एवं हिन्दी के प्लेकार्ड वितरीत किये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रदेश फैडरेशन अपनी पोशाक रख सकती है, टी–शर्ट, टोपी, स्कार्फ आदि आदि अपने भागीदारों को देकर।
- हमारी माँगों पर नारे लगाये जा सकते हैं जो कि बैंकिंग सुधार उपायों के विरूद्ध हों।
- सभी भागीदारों को सलाह और चेतावनी दें कि वह अपने बटुए, पर्स, मोबाईल फोन, घड़ी आदि का ध्यान रखें क्योंकि पिछले अवसरों के हमारे कटु अनुभव हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री